













प्रमुख तेल उत्पादक देश यूएई ने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने की घोषणा की है। ओपेक में यह टूट उस कार्टेल के लिए बड़ा झटका है जो उत्पादन को नियंत्रित करके वैश्विक बाजार में अपने हितों के हिसाब से कीमतें तय करने के लिए काम कर रहा था। भारत समेत तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर देशों को इससे फायदा हो सकता है क्योंकि अब यूएई अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल करते हुए तेल निर्यात की मात्रा बढ़ा सकता है। वैश्विक बाजार में ज्यादा आपूर्ति का मतलब है तेल की कीमतों में कमी। पश्चिम एशिया में जारी बर्खास्त के कारण ऊंची तेल कीमतों के बीच यह घटनाक्रम भविष्य में तेल का गणित बदल सकता है। ऐसे समय में जब दुनिया भर में तमाम देश जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जीवाश्म ईंधन के उत्पादक देशों में यह सोच भी बन रहा है कि हो सकता है भविष्य में तेल की यह कीमत न रह जाए जो आज है। ऐसे में वे अगले एक दो दशक में अपने संसाधनों को तेजी से दोहन करने की रणनीति पर आगे बढ़ सकते हैं। ओपेक में टूट से तेल की आपूर्ति और कीमतों पर असर और भारत के लिए इसके निहितार्थ की पड़ताल आज अहम मुद्दा है...



# अब और गहरे होंगे भारत-यूएई के बीच ऊर्जा संबंध

विश्व के सबसे अस्थिर क्षेत्र पश्चिम एशिया में एक बड़े फिर नया भूचल आ गया है, जिसके व्यापक क्षेत्रीय एवं वैश्विक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ईरान, ईरान और ओपेक-प्लस के बीच चल रहे युद्ध और संघर्षों के बतवारा में खाड़ी के प्रमुख देश संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) ने कच्चे तेल के निर्यातक देशों के समूह ओपेक एवं ओपेक प्लस से एक मई 2026 से स्वयं को अलग करने की घोषणा कर दी है। मौलानब है कि अमीरात, जो इस समूह के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, का इस गूट से बाहर निकलना न केवल वैश्विक तेल आपूर्ति पर ओपेक के नियंत्रण को कमजोर करता है, बल्कि अमीरात और उसके पड़ोसी सऊदी अरब के बीच चल रहे तनाव को भी गहरा करता है। सऊदी अरब प्रभावित रूप से ओपेक और खाड़ी संयुक्त परिदृश्य (जीसीसी) का नेतृत्व करता है। हालांकि, यूएई के इस निर्णय के प्रभावों को लेकर विश्लेषकों के अलग-अलग मत हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया को अभी भी तेल के हर डालख बरेल का आश्रयकता है। अमीरात अकेले ही विश्व का अठारहवां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और वैश्विक तेल उत्पादन में इसकी लगभग चार प्रतिशत हिस्सेदारी है। लेकिन इस निर्णय के पीछे के कारण, स्वयं इस कदम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसमें आर्थिक एवं भू-राजनीतिक दोनों कारण शामिल हैं, और ईरान युद्ध ने इन दोनों को जोड़ने में मदद की है। दरअसल, यूएई जैसे अमीरात तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए धरती निर्यात कर रहा है। वह लगभग 150 अरब अमेरिकी डालर खर्च कर अपनी दैनिक उत्पादन क्षमता को 50 लाख बैरल के करीब ले जाने की दिशा में काम कर रहा है। लेकिन ओपेक के कोट नियमों के कारण यह इस क्षमता का पूरे तरह उपयोग नहीं कर पा रहा है। उसका वास्तविक उत्पादन क्षमता में लगभग 35 लाख बैरल प्रतिदिन ही बना हुआ है। यह उत्पादन ओपेक की क्रेटा प्रणाली द्वारा सीमित है, जिसका उद्देश्य आपूर्ति को नियंत्रित कर कीमतों को स्थिर रखना है। यूएई में यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि यदि तेल बेचने के अनुमति नहीं है, तो उत्पादन क्षमता बढ़ाने में इतना निवेश क्यों किया गया?



पवन चौरसिया  
रिस्वर्च एंड  
एडिटोरियल एडवाइजर

**अब भारत यूएई के साथ ऊर्जा आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते कर सकता है। भौगोलिक दूरी का भेद होने की वजह से परिवहन लागत भी कम होगी। आने वाले समय में भारत-यूएई के बीच ऊर्जा संबंध और गहरे हो सकते हैं।**

ओपेक से निकलना सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं है, बल्कि यह बदलती राजनीतिक और सुरक्षा गणनाओं को भी दर्शाता है। ईरान युद्ध के दौरान यूएई पर हुए हमलों के बाद अरब शक्ति में यह सुरक्षा बढ़ी है कि जीसीसी जैसे क्षेत्रीय संगठनों ने उसे सीमित समर्थन ही दिया है। इस अनुभव के कारण उम्मेद अमीरात निती को अन्य अरब देशों की तुलना में अधिक स्वतंत्र बनाना शुरू कर दिया है। इसी दिशा में उसने 2020 के अरबम सझौते के आधार पर अमेरिका और इराक के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। अमीरात के अलावा होने से ओपेक के अधिकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक समय वह समूह वैश्विक तेल उत्पादन के आधे से अधिक हिस्से को नियंत्रित करता था, जो आज धक्कर लगभग 35 प्रतिशत रह गया है। कुछ विश्लेषकों इसे अमेरिका की जीत बना रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी गणराज्य तेल की ऊंची कीमतों के लिए ओपेक को बच-बचा आलोचना कर रहे हैं।

भारत के संदर्भ में इसके दो स्पष्ट परवर्ध हो सकते हैं। यूएई द्वारा उत्पादन बढ़ाए जाने से वैश्विक बाजार में कीमतों का भी अभाव होगा और प्रायः अब यूएई के साथ सीधे दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते कर सकता है। यूएई में भौगोलिक रूप से भारत के करीब है, इसलिए परिवहन लागत कम होगी और आयात बिल में बचत होगी। यह कदम अमेरिकी श्रेष्ठतम प्रणाली को और बढ़ाने में भी मदद कर सकता है, जहां देश तेल उत्पादन के लिए फेब्रुअरी 2024 में निर्णय लेने के बजाय अपने वैश्वीय मुद्दों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि हमें जल्द ही जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों को देखना पड़ेगा और जटिल विषय होंगे। फिर भी, यह निर्णय भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक मामला के साथ गहरे ऊर्जा संबंध स्थापित करने का बड़ा रास्ता खोलता है।

## यूएई ने क्यों छोड़ा ओपेक

**संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) ने एक मई 2026 को ओपेक और ओपेक प्लस की अपनी 59 साल पुरानी संस्थापक आधिकारिक रूप से समाप्त कर दी। यह वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है, क्योंकि यूएई पहला महा-उत्पादक देश है जिसे इस कार्टेल को छोड़ना है। यूएई वैश्विक आपूर्ति का लगभग बराबर योगदान देता है। यह निर्णय वैश्विक आर्थिक रणनीति व तकनीकी भू-राजनीतिक अग्र का मिनटाला नतीजा है।**

## भू-राजनीतिक तनाव

सऊदी अरब के साथ तनाव हाल ही में चरम पर पहुंच गया है। यूएई के अतिवाकियों ने ईरान के साथ चले रहे सऊदी के दौरान खाड़ी सहयोगियों से अपेक्षित समर्थन में मित्रों पर नाराजगी जताई, जिन्होंने सऊदी उर्जा स्रोत पर हमलों भी शामिल हैं।

## उत्पादन की स्वतंत्रता

यूएई ने 2027 तक अपनी उत्पादन क्षमता 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए 150 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। ओपेक का कोटा इस निवेश का पूरा लाभ उठाए बिना बचाना नहीं है। अब यूएई इस बाधा को दूर कर चुका है।

## आर्थिक राहत

**कम आयात बिल-निर-ओपेक यूएई से बड़ी आपूर्ति वैश्विक कीमतों पर गिरावट का वचाव बल सकता है, खासकर जब क्षेत्रीय तनाव कम होगा।**

## रुपये में तेल व्यापार और डी-डालरराइजेशन

यूएई के इस कदम से रणनीतिक मुद्दा में व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। भारत और यूएई पहले ही रुपये और डॉलर में तेल भुगतान पर चर्चा कर चुके हैं। ओपेक से बाहर होने के कारण, जो पारंपरिक रूप से अमेरिकी डॉलर को प्राथमिकता देता है, यूएई अब रणनीतिक मुद्दा-आधारित साझेदारी को और गहरा कर सकता है, जिससे भारत की वलायत पर निर्भरता कम होगी।

## रुपये में तेल व्यापार और डी-डालरराइजेशन

यूएई के इस कदम से रणनीतिक मुद्दा में व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। भारत और यूएई पहले ही रुपये और डॉलर में तेल भुगतान पर चर्चा कर चुके हैं। ओपेक से बाहर होने के कारण, जो पारंपरिक रूप से अमेरिकी डॉलर को प्राथमिकता देता है, यूएई अब रणनीतिक मुद्दा-आधारित साझेदारी को और गहरा कर सकता है, जिससे भारत की वलायत पर निर्भरता कम होगी।

## अर्थव्यवस्था का विविधीकरण

यूएई ने एक अर्थव्यवस्था को और बढ़ा रहा है, जिसमें एआइ और नौकरशाही के उर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ओपेक से बाहर आकर वह देश क्षेत्रों में निवेश के लिए अधिकतम तेल राजस्व प्राप्त करना चाहता है।

## भारत के लिए रणनीतिक प्रभाव

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता होने के नाते भारत यूएई के इस फैसले का सबसे बड़ा लाभार्थी बन सकता है।

## ओपेक से बाहर हुआ यूएई

ओपेक से अलग होने का यूएई का फैसला तेल उत्पादन को अधिकतम कर रहे हैं जहां की रणनीति का हिस्सा है।

## 14 सितंबर 1960 ओपेक की स्थापना

ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी।

## 38% ओपेक का उत्पादन प्रति दिन



## 80% वैश्विक तेल भंडार में हिस्सेदारी

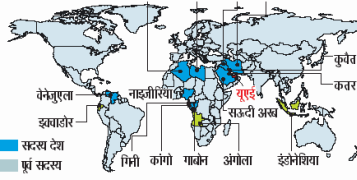
समूह का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है

## 50% वैश्विक तेल निर्यात में हिस्सेदारी

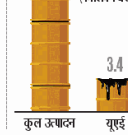
66 अरब डॉलर निवेश किए हैं यूएई ने हाल में तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने में

## 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक उत्पादन बढ़ाकर

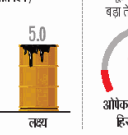
उत्पन्न लक्ष्य तेल उत्पादन बढ़ाकर



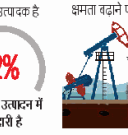
## ओपेक का उत्पादन प्रति दिन



## ओपेक में यूएई की हिस्सेदारी



## वैश्विक तेल भंडार में हिस्सेदारी



## वैश्विक तेल निर्यात में हिस्सेदारी



## आफ़ी आवाज

दुनिया में किसी भी वस्तु की कीमतें मांग और आपूर्ति पर तय होती हैं। अगर किसी वस्तु का उत्पादक की मांग अधिक होती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं और अगर मांग मिनटों में तेजी से कम हो जाती है तो उसकी कीमतें घट जाती हैं। इसी तरह वस्तु की आपूर्ति का हलका होना या ज्यादा होने से भी कीमतें बढ़ती घटती हैं। ओपेक के देशों ने तेल की कीमतों को अपने हितों के हिसाब से तय करने के लिए उत्पादकों को हदियायत बनाया। वे इस देश से अतिरिक्त कर सके क्योंकि वैश्विक तेल निर्यात में बड़े हिस्सेदारी वाली देशों की है। एक तरह से ये देश कार्टेल का काम कर रहे हैं। अब यह कार्टेल टूट गया है।

## ओपेक का उत्पादन प्रति दिन

ओपेक के देशों ने तेल की कीमतों को अपने हितों के हिसाब से तय करने के लिए उत्पादकों को हदियायत बनाया। वे इस देश से अतिरिक्त कर सके क्योंकि वैश्विक तेल निर्यात में बड़े हिस्सेदारी वाली देशों की है। एक तरह से ये देश कार्टेल का काम कर रहे हैं। अब यह कार्टेल टूट गया है।

# ओपेक समूह में टूट से तेल के खरीदार देशों को होगा फायदा



अरुण शर्मा  
पूर्व सौलक्ष्य, ओपेकनीती

**यूएई के ओपेक से बाहर आने से तेल की कीमतें गिरेंगी और भारत सहित तेल के बड़े आयातक देशों को फायदा होगा। ओपेक तेल समूह में अपने हितों के अनुसार आपूर्ति तय कर रहा है। जब यूएई अपने हितों को ध्यान में रखकर तेल की कीमतें तय करेगा तो तेल कीमतों में कमी आएगी।**

ऊर्जा उद्योगों के लिए काफी हद तक आपूर्ति पर निर्भर हैं, ऊर्जा के वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। ओपेक के देशों को फायदा होगा। ओपेक तेल समूह में अपने हितों के अनुसार आपूर्ति तय कर रहा है। जब यूएई अपने हितों को ध्यान में रखकर तेल की कीमतें तय करेगा तो तेल कीमतों में कमी आएगी।

ऊर्जा उद्योगों के लिए काफी हद तक आपूर्ति पर निर्भर हैं, ऊर्जा के वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। ओपेक के देशों को फायदा होगा। ओपेक तेल समूह में अपने हितों के अनुसार आपूर्ति तय कर रहा है। जब यूएई अपने हितों को ध्यान में रखकर तेल की कीमतें तय करेगा तो तेल कीमतों में कमी आएगी।

यूएई के ओपेक से बाहर आने से तेल की कीमतें गिरेंगी और भारत सहित तेल के बड़े आयातक देशों को फायदा होगा। ओपेक तेल समूह में अपने हितों के अनुसार आपूर्ति तय कर रहा है। जब यूएई अपने हितों को ध्यान में रखकर तेल की कीमतें तय करेगा तो तेल कीमतों में कमी आएगी।

ऊर्जा उद्योगों के लिए काफी हद तक आपूर्ति पर निर्भर हैं, ऊर्जा के वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। ओपेक के देशों को फायदा होगा। ओपेक तेल समूह में अपने हितों के अनुसार आपूर्ति तय कर रहा है। जब यूएई अपने हितों को ध्यान में रखकर तेल की कीमतें तय करेगा तो तेल कीमतों में कमी आएगी।

ऊर्जा उद्योगों के लिए काफी हद तक आपूर्ति पर निर्भर हैं, ऊर्जा के वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। ओपेक के देशों को फायदा होगा। ओपेक तेल समूह में अपने हितों के अनुसार आपूर्ति तय कर रहा है। जब यूएई अपने हितों को ध्यान में रखकर तेल की कीमतें तय करेगा तो तेल कीमतों में कमी आएगी।

ऊर्जा उद्योगों के लिए काफी हद तक आपूर्ति पर निर्भर हैं, ऊर्जा के वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। ओपेक के देशों को फायदा होगा। ओपेक तेल समूह में अपने हितों के अनुसार आपूर्ति तय कर रहा है। जब यूएई अपने हितों को ध्यान में रखकर तेल की कीमतें तय करेगा तो तेल कीमतों में कमी आएगी।

## चेन्नई हवाई अड्डे पर विमान के आपात द्वाार से यात्री कूदा

**चेन्नई एरलाइंस: शासन ने चेन्नई हवाई अड्डे पर अरबिया का विमान जल-दुर्घटना से बचाने के लिए आपातकालीन प्रस्ताव पेश किया है।**

**सीआरएआरएफ की मदद से एयर अरबिया के यात्री को पुलिस ने हिरासत में लिया।**

चेन्नई एरलाइंस: शासन ने चेन्नई हवाई अड्डे पर अरबिया का विमान जल-दुर्घटना से बचाने के लिए आपातकालीन प्रस्ताव पेश किया है।

सीआरएआरएफ की मदद से एयर अरबिया के यात्री को पुलिस ने हिरासत में लिया।

## शिमला के सरकारी नर्सिंग संस्थान के हास्टल में 30 की कक्षा, ठहराई थी 80 प्रशिक्षु

**शिमला जिले के रसपुर के खन्नी स्थित मालाया प्राई विद्यालय से संबंधित शिमला के सरकारी नर्सिंग संस्थान के हास्टल में 30 की कक्षा, ठहराई थी 80 प्रशिक्षु।**

## जयपुर में लश्कर आतंकी ने बनवाया था फर्जी वोटर कार्ड

**जयपुर में लश्कर आतंकी ने बनवाया था फर्जी वोटर कार्ड।**

## राष्ट्रीय फलक

राष्ट्रीय फलक

## शिमला के सरकारी नर्सिंग संस्थान के हास्टल में 30 की कक्षा, ठहराई थी 80 प्रशिक्षु

शिमला के सरकारी नर्सिंग संस्थान के हास्टल में 30 की कक्षा, ठहराई थी 80 प्रशिक्षु।

## जयपुर में लश्कर आतंकी ने बनवाया था फर्जी वोटर कार्ड

जयपुर में लश्कर आतंकी ने बनवाया था फर्जी वोटर कार्ड।













